बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 102

पांच वर्ष का बजट

वित्त मंत्री चुनिंदा समूहों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रही हैं। ऐसी बैठकों में आमंत्रित व्यक्ति या समूह ढेर सारे विचार प्रकट करते हैं। इनमें अच्छे विचार भी होते हैं और बुरे भी। यही कारण है कि ऐसी बैठकों में प्रस्तुत विचारों में से बहुत कम विचार बजट का हिस्सा बन पाते हैं। परंतु यहां उठाए जाने वाले मुद्दों से वित्त मंत्री प्रभावित अवश्य होते हैं क्योंकि इन मुद्दों को मुद्रास्फीति, घाटे या आर्थिक वृद्धि जैसे विषयों पर आम जनता के विचार माना जाता है।

राजकोषीय स्थिति तनावपूर्ण है, आर्थिक वृद्धि में धीमापन आया है, कर राजस्व अनुमान से कम है और उचित आकलन किया जाए तो घाटा ज्यादा है। सरकार का कर्ज भी अपेक्षित स्तर से 20 फीसदी अधिक है और नई उधारी तमाम आम बचत को समाप्त कर रही है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि इस बचत में कमी आई है। निजी क्षेत्र के लिए कोई बचत उपलब्ध नहीं है। स्वाभाविक बात है कि रिजर्व बैंक के लिए बाजार में ब्याज दर कम करना कठिन है। फंड की कमी और उसकी लागत के चलते निवेश प्रभावित हुआ है।

मुद्रास्फीति की औसत दर बीते वर्षों में 7 फीसदी से घटकर 3 फीसदी हो गई है लेकिन भविष्य निधि जैसी बचत योजनाएं अभी भी शून्य जोखिम पर 8 फीसदी से अधिक का करमुक्त प्रतिफल दे रही हैं। यह दर बहुत ज्यादा है और मुद्रा बाजार के साथ सुसंगत नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद वास्तविक ऋण दर दुनिया की सर्वोच्च दरों में शामिल है। अगर सरकार ब्याज दरों में कमी चाहती है और निजी निवेश को सुविधा देती है तो उसे कुछ अन्य कदम उठाने के साथ अल्प बचत पर कर प्रोत्साहन समाप्त करना होगा। व्यय क्षेत्र में उसे न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए।

भारी बहुमत से चुनकर आई हुई नई सरकार किसी तरह की सलाह सुनना नहीं चाहती। पिछले वर्ष से तुलना की जाए तो इस वर्ष की नई या बड़ी प्रतिबद्धताओं में आयुष्मान भारत योजना की लागत और किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक देने जैसी बात शामिल है। ऐसा तब है जबकि कर राजस्व बजट में उल्लिखित आंकड़ों से बेहद कम है। बीते वर्षों के दौरान रक्षा व्यय संकुचित हुआ है और वित्त मंत्री को रक्षा मंत्रालय में अपने पिछले कार्यकाल से यह पता ही होगा कि सेनाओं को उपकरणों के मामले में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी अनदेखी आगे भारी पड़ सकती है। पिछले वर्ष के तमाम ऐसे बिल हैं जिन्हें चुकता किया जाना है। बजट के व्यय क्षेत्र को लेकर रुख में नरमी लानी होगी। कोई भी नया या अतिरिक्त व्यय अन्य मद की बचत के अनुरूप होना चाहिए। ऐसी बचत हमेशा संभव रहती है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

राजस्व पक्ष की बात करें तो धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था में नए कर बढ़ाने की संभावना सीमित है। कठोर यथार्थ यह है कि वित्त मंत्री के पास कुछ खास राजकोषीय गुंजाइश नहीं है। उनके पास केवल रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त भंडार के रूप में स्थानांतरित राशि ही अतिरिक्त होगी। चूंकि वित्तीय क्षेत्र की दिक्कत अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती रहेगी और बैलेंस शीट सुधार का काम अभी प्रक्रिया के अधीन है इसलिए आरबीआई से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस राशि का इस्तेमाल अन्यथा मजबूत शैडो बैंकों को विशेष वित्त मुहैया कराने के लिए किया जाना चाहिए। ये संस्थान नकदी की तंगी से जूझ रहे हैं।

सबसे बेहतर नीति यह होगी कि वित्त मंत्री आगे बढ़कर सच्चाई को सामने रखें। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह पंचवर्षीय टेस्ट मैच खेल रही हैं, न कि एकदिवसीय मैच। उनका ध्यान राजकोषीय शुचिता और नियंत्रण पर रहना चाहिए (वित्तीय बाजार इसका स्वागत करेंगे) इसके साथ ही उन्हें दीर्घावधि के सुधार वाली नीतिगत पहल के साथ लोगों में ऊर्जा का संचार करना चाहिए। सरकारी खाद्य खरीद प्रक्रिया में सुधार करके सब्सिडी बिल कम किया जा सकता है। जब हर वर्ष अधिशेष अन्न उत्पादित हो रहा है तो बफर स्टॉक की आवश्यकता नहीं है। बुनियादी निवेश की फंडिंग मौजूदा परिसंपत्तियों मसलन सड़क, बिजली वितरण कंपनियों आदि के संचालन और रखरखाव के दीर्घावधि के अनुबंधों के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह हासिल धन राशि का इस्तेमाल नई परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जा सकता है। ऐसा उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां शुरुआती परियोजना जोखिम सरकार का होता है।

5 जी की आकांक्षा और हकीकत

सरकार 5 जी सेवाओं और डिजिटल इंडिया के लिए क्या कुछ कर सकती है, इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं **श्याम पोनप्पा**

देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत का विचार हममें से कई को उत्साहित कर सकता है। 5जी तकनीक आखिर है क्या? यह दरअसल दूरसंचार प्रौद्योगिकी का मिश्रण है जहां कहीं अधिक तेज गति वाले डेटा को व्यापक गहन और बेहतर संचार के साथ उपलब्ध कराया जाता है। जबकि इस दौरान ऊर्जा की खपत होती है और बैटरी की अवधि में इजाफा होता है। जाहिर तौर पर यह विकिरण भी कम करता है। लब्बोलुआब यह कि इसकी सहायता से लोग सहज ढंग से और किफायत से अपने काम कर सकेंगे। इसकी सहायता से स्मार्ट फोन से लेकर कंप्यूटर तक, अध्ययन, कार्यालयीन कार्य, शोध, मनोरंजन से लेकर घर-दफ्तर में विभिन्न उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल सहज और सुविधाजनक हो सकता है। आगे बात करें तो यह रेफ्रिजरेटरों, खाना पकाने के उपकरण, औद्योगिक उपकरण, परिवहन आदि के क्षेत्र में भी जीवन को कहीं अधिक आसान बना सकता है। 5जी एक लंबी प्रक्रिया के शुरुआती चरण में है। शायद देश में इसका व्यापक परीक्षण होने में अभी कुछ वर्ष का समय लग जाए। व्यापक उपलब्धता में इससे भी अधिक वक्त लग सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 100 अरब डॉलर का निवेश करना होगा।

इसके अलावा तमाम ऐसी वजह हैं जिनके चलते देश की क्षमताओं में इजाफा जरूरी है। अब यह आवश्यक हो चला है कि हम आयात पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जरूरतें खुद पूरी करें। अगर हम चाहते हैं कि पेट्रोलियम आयात हमारे भुगतान संतुलन पर नकारात्मक असर नहीं डाले तो उसके लिए घरेलू क्षमताओं का विकास करना एक तरह की पूर्व शर्त है। बिना घरेलू क्षमताओं के ऊर्जा आयात इलेक्ट्रॉनिक आयात को भी सीमित करेगा। इससे पता चलता है कि हमें सौर ऊर्जा विकास की किस कदर आवश्यकता है।

बहरहाल, देश के संचार उद्योग की वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। क्षमताओं के विकास के लिए राजस्व अर्जित करना और इक्विटी और डेट के संदर्भ में पूंजी तक पहुंच सुनिश्चित करना, दोनों आवश्यक हैं। यह भी अनुकूल दर पर होना चाहिए। दूरसंचार क्षेत्र में कीमतों की जंग के बाद रिलायंस जियो भी अपने कर्मचारियों की तादाद कम कर रही है। इस बीच एयरटेल ने 4जी के बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है लेकिन वह तब तक 5जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने का अनिच्छुक नजर आता है जब तक कि कीमतों में कमी नहीं आती है।

सरकार ने सितंबर 2015 में 5जी के लिए एक समिति गठित की थी। इसकी अध्यक्षता स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय के मानद प्रोफेसर आरोग्यस्वामी पलराज को दी गई थी जो बेतार संचार विषय में प्रवीण हैं। इस समिति ने अपनी अनुशंसा में कहा कि नेटवर्क तात्कालिक प्राथमिकता है। उसके अनुसार ऐसा करके ही 5जी नेटवर्क को शीघ्र और किफायती अंदाज में शुरू किया जा सकेगा। बाद के चरणों के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और निर्माण क्षमता की अनुशंसा की गई।

नेटवर्क तैयार करने के लिए नीतिगत समर्थन आवश्यक होता है। खासतौर पर कर्ज के बोझ तले दबे क्षेत्र के लिए जिसका प्रति उपभोक्ता राजस्व लगातार कम हो रहा हो, स्पेक्ट्रम तक जिसकी पहुंच नहीं हो। हालांकि इस बीच अन्य देशों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यह विडंबना ही है क्योंकि भारत इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति और बड़ा बाजार है। इसके बावजूद सरकार की नीतियां बहुत अधिक सफल साबित नहीं हुई हैं।

सरकार ने 5जी के क्षेत्र में बढ़त बनाने की बात कही थी। इसके बावजूद भारत इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है।

स्पेक्ट्रम आवंटन और बड़े परीक्षण 2019 के अंत तक होने थे जबकि नीलामी 2020 तक होनी थी। बहरहाल, सरकार ने कहा है कि सितंबर तक 5जी परीक्षण और 2019 के अंत तक नीलामी की जाएगी। चूंकि अभी स्पेक्ट्रम बैंड के विकल्प और परीक्षण के लिए आवंटन अभी होना है इसलिए ऐसे तमाम मसलों को हल किए बिना इस दिशा में आगे बढ़ना दिक्कतदेह हो सकता है।

इसके अलावा हमारे देश में स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य कोरिया की तुलना में सात गुना है। क्षेत्रवार नकद प्रवाह कमजोर है और ग्राहक ऐसे हैं जो बहुत सस्ती सेवाएं चाहते हैं। एकाधिकार वाली व्यवस्था सार्वजनिक हित में नहीं होगी। ऐसे में वायरलेस रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क स्थापना और बाजार विकास का बेहतर विकल्प हो सकता है।

पता नहीं क्यों सरकार और आम जनता अभी भी संचार को सरकारी दुधारू गाय की तरह समझते हैं जबकि हकीकत में यह एक अहम बुनियादी ढांचा है। इस बीच कम निवेश और खराब सेवाओं का रोना भी रोया जाता है। सरकार की ओर से भारी भरकम शुल्क भी निवेश को कम करते हैं। राजस्व के करीब 29 से 32 फीसदी के अलावा वह कॉर्पोरेट कर भी लेती है। सरकार इसमें बदलाव ला सकती है या फिर वह 5जी और संचार सेवाओं की स्थापना से जुड़ी बढ़त को गंवा सकती है।

कैसे हो शुरुआत

सरकार निम्नलिखित कदम उठाकर इस काम को गति प्रदान कर सकती है:

- संचार क्षेत्र के बुनियादी क्षेत्र होने के नाते ऋण की लागत और कर दर कम करना। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 के इस लक्ष्य की अनदेखी की गई है।
- वैश्विक आवंटन के अनुरूप पर्याप्त स्पेक्ट्रम आवंटित करना। चूंकि देश में फाइबर का विस्तार सीमित है और डिजिटल प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है इसलिए तमाम स्पेक्ट्रम और बुनियादी ढांचे तक साझा पहुंच हो और उपयोग शुल्क राजस्व साझेदारी पर आधारित हो।
- प्रशासनिक गतिरोध को समन्वय और उचित प्रक्रिया के आधार पर बिना किसी देरी के समाप्त किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 12 महीने के परीक्षण के लिए तत्काल स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाना चाहिए।

कई देशों ने 5जी स्पेक्ट्रम सेवा शुरू करने का काम आरंभ भी कर दिया है। इनमें कोरिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, इटली और जापान शामिल हैं। इन देशों में करीब 500 5जी केंद्र हैं।

5 जी आकांक्षाएं और हकीकत

भारत में इस संदर्भ में हुआवे की भूमिका विवादास्पद है। एक मसला गैरभेदकारी कारोबारी शर्त या प्रतिस्पर्धा में स्पष्टता का है। अगर हुआवे जैसी संस्था सरकार की मदद से वैश्विक दबदबा कायम करती है तो वह उन शर्तों पर संचालन कर सकती है जिनका मुकाबला कोई और नहीं कर पाएगा। ऐसे संस्थान बहुत आसानी से किसी भी मुल्क में दबदबा कायम कर सकते हैं। हुआवे भले ही नोकिया या एरिक्सन से अलग कुछ नहीं कर रही है लेकिन उसे हमारे ऐसे पड़ोसी देश का समर्थन हासिल है जिसका व्यवहार दबदबे वाला है। ऐसे में उस पर निर्भरता ठीक नहीं।

डिजिटल इंडिया और 5जी में सफलता पाने के लिए सरकार संचार क्षेत्र को बुनियादी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करके शुरुआत कर सकती है। उसे स्पेक्ट्रम और नेटवर्क साझेदारी का इस्तेमाल करते हुए संसाधनों का भरपूर प्रयोग करना चाहिए तथा स्थानीय तकनीक का भरपूर सहयोग लेना चाहिए।

राजनाथ के समक्ष अनियमितताएं दुरुस्त करने की चुनौतियां

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

जब राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडलीय समितियों- राजनीतिक मामलों और संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समितियों- से बाहर रखा गया तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। दूसरी तरफ टेलीविजन चैनलों पर मंत्रिमंडल में कथित तौर पर उनका कद कम किए जाने की चर्चाएं जोर-शोर से चल रही थीं। हां, सरकार में कायदे से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद इन दोनों समितियों में जगह नहीं मिलने पर थोड़ा आहत होने का हल्का सा इशारा उन्होंने तब दिया जब उन्होंने अपने एक सहयोगी से पूछा, 'क्या अब तुम्हें मैं छह फुट के बजाय पांच फुट का दिखता हूं।' शाम तक सरकार ने अपना निर्णय बदला और अधिसूचना दोबारा जारी की। राजनाथ कभी इस्तीफा का संकेत देते या पेशकश करते या ऐसा करने की धमकी देते नजर नहीं आए।

अनुशासन उनकी एक खास पहचान रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनने से लेकर रक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति में दूसरी बार शामिल किए जाने तक राजनाथ ने उम्दा एवं उपलब्धियों से भरपूर सफर तय किया है। वह उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री, साथ ही प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष रह चुके हैं। राजग सरकार में वह कई बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके हैं।

राजनाथ आपातकाल के दौरान जनसंघ की छात्र इकाई से जुड़े रहे और मात्र 26 वर्ष की उम्र में 1977 में मिर्जापुर से विधायक चुने गए थे। 1980 के दशक के आखिरी दौर और 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का जोर था और उन्होंने 1991 में राजनाथ को शिक्षा मंत्री बनाया था। शिक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने सबसे पहले एक अध्यादेश के जरिये ऐंटी-कॉपिंग (नकल रोधी) कानून लेकर आए, जिससे सामग्री चोरी करना गैर-जमानती अपराध हो गया। इसका मतलब यह था कि स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर थी। यह कानून आने के बाद 14 से 15 वर्ष के बच्चे नकल करने के जुर्म में जेल भेजे जा रहे थे। 1991 में उत्तर प्रदेश उच्च विद्यालय बोर्ड परीक्षा में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले बच्चों का प्रतिशत 58.03 था। नकल रोधी कानून आने के बाद 1992 में यह आंकड़ा कम होकर 14.7 प्रतिशत रह गया। राजनाथ को इसका खमियाजा भुगतान पड़ा। उन्होंने लखनऊ के निकट छात्रों की बहुलता वाली मोहाना सीट से 1993 में विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 1994 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। बाद में वह वाजपेयी और मोदी सरकार में मंत्री बने।

अनुशासन का पालन करने की खूबी हमेशा उनकी खास पहचान रही है और अब वह देश के रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। वह एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सैनिकों को उनका हक और सम्मान दिलाने, नागरिक अफसरशाही की दखलंदाजी रोकने और रक्षा नीतियों में सेना को पर्याप्त भागीदारी देने के वादों के साथ सत्तारूढ़ हुई है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा ताने-बाने के अपभंग और नागरिक समाज और सेना के बीच संबंधों में अविश्वास के बीज स्वतंत्रता के समय बोए गए थे जब ब्रिटिश काल की सेना की औपनिवेशिक एकीकृत कमान एक राष्ट्रीय सेना में तब्दील हो रही थी। संबंधों में अविश्वास की जड़ कमांडर-इन-चीफ किचनर और वायसराय कर्जन के बीच बार-बार पैदा होने वाले विवाद से जुड़ी है। कर्जन वित्तीय नियंत्रण अपने हाथों में रखने के लिए अपने कार्यकारी परिषद में एक अतिरिक्त सदस्य रखना चाहते थे, लेकिन किचनर इसके खिलाफ थे। अब करीब 150 वर्ष बाद भी उस विवाद की विरासत पीछा नहीं छोड़ रही है।

सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी को छोड़कर भारत के किसी भी नेता के पास सैन्य अनुभव नहीं था। स्वतंत्रता के बाद एक बात जिसका सबसे डर सता रहा था वह था तख्तापलट का। मौजूदा सेना विभाग सबसे पहले रक्षा विभाग और बाद में रक्षा मंत्रालय में तब्दील किया गया। उस समय रक्षा सचिव एच एम पटेल और उनके दो अन्य उत्तराधिकारियों ने सेना मुख्यालयों को रक्षा मंत्रालय के साथ जोड़ने की पेशकश की। जनरल राजिंदरसिंहजी और जनरल के एस थिमैया ने इसके लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि मंत्रालय के साथ जुड़ने से उनके हाथ से परिचालन नियंत्रण फिसल जाएगा।

जल्द ही सेना जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और गोवा कार्रवाई में लग गई। हालांकि इसकी प्रतिष्ठा जरूर बढ़ी, लेकिन प्रभाव कम होता गया। बात यहां तक पहुंच गई कि महत्त्वपूर्ण कार्रवाई से जुड़े विषयों में सेना की राय भी नहीं ली गई। नागरिक अफसरशाही और राजनीतिक नेतृत्व ने सेना के तीनों अंगों को छोटा कर दिया। उस समय सेना के जनरल अपना कद छोटा होने की कवायद से बेफिक्र और अनजान थे, जबकि दूसरी तरफ अफसरशाही अपना नियंत्रण मजबूत करती चली गई और 'फूट डालों और राज करो' की नीति पर काम करने लगी। उन्होंने सेना के तीनों अंगों में आपसी समन्वय एवं सहमति पनपने नहीं दी और मंत्रालय के साथ इनके एकीकरण के प्रस्ताव को आगे बढ़ने नहीं दिया।

इस तरह, सेना में स्थिति बन गई कि वरीयता क्रम में गिरावट से लेकर वित्तीय एवं परिचालन स्वायत्तता में कमी आई। पदोन्नति, पदस्थापना और यहां तक कि कैंटीन के मुनाफे का वितरण भी बदतर होते हालात की चपेट में आ गए। एक समय रक्षा मंत्रालय ने पदोन्नति परीक्षा की भी जांच करने को कहा, लेकिन मंत्रालय को बताया गया कि यह एक पेशे से जुड़ा मामला है।

राजनाथ को रक्षा मंत्री के रूप में इन अनियमितताओं को दुरुस्त करना है, लेकिन सवाल है कि क्या अनुशासन आड़े आएगा?

कानाफूसी

राज्यपाल कौन?

अगले तीन महीनों में देश भर के नौ राज्यपाल सेवानिवृत्त होने वाले हैं क्योंकि उनका पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। इनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ और मिजोरम में यह पद रिक्त है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ही राज्यपाल है। संभावना यह है कि कुछ राज्यपाल दोबारा नियुक्त किए जाएं। अटकलें तो यह भी हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं मसलन सुषमा स्वराज, उमा भारती और सुमित्रा महाजन को राज्यपाल बनाया जा सकता है। इन तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। स्वराज का नाम उस समय चर्चा में आ गया था जब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने ट्विटर पर उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल 'नियुक्त' किए जाने की बधाई दे दी थी। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट हटा दिया था।

कमलनाथ पर सवाल

मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक आधिकारिक वक्तव्य जारी करके कहा कि उसने 4,000 करोड़ रुपये के छह निवेश प्रस्तावों को सात दिन से भी कम समय में मंजूरी दी है। इसी बीच आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस ने दुबे को विधानसभा चुनाव के पहले आरटीआई इकाई का अध्यक्ष बनाया था जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर मुख्यमंत्री से कहा कि वह जनवरी 2019 में अपनी दावोस यात्रा के बाद से प्रदेश में आए निवेश की जानकारी साझा करें। कमलनाथ ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की थी। दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वहां से आने के बाद काफी निवेश आने की बात कही थी लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ।

आपका पक्ष

अंतरिक्ष में भी भारत का होगा दबदबा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष में अपना केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। अगर यह योजना सफल होती है तो अगले पांच से सात साल में भारत का अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा। इससे भारत अधिक से अधिक मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज सकेगा। अभी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) कई देशों के सहयोग से चल रहा है लेकिन मुख्य भूमिका अमेरिका की है। आईएसएस को चलाने में काफी राशि खर्च होती है जिसमें कई देश सहयोग करते हैं। चीन भी अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इसरो के मुताबिक भारत का अंतरिक्ष केंद्र 20 टन होने की संभावना है। इसरो ने इसकी लागत का खुलासा नहीं किया है। तकनीक के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में इसरो भी काफी तेजी से कार्य कर रहा है। कई देशों के सैटेलाइट इसरो की मदद से प्रक्षेपित किए जाते हैं।

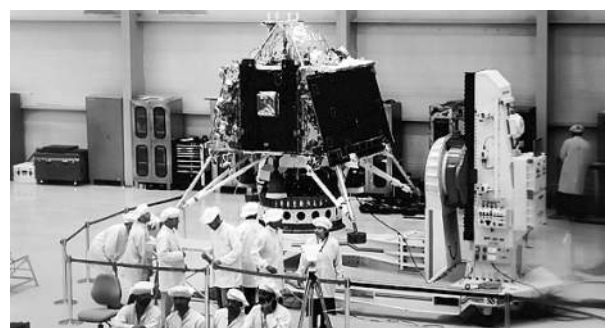

भारत ने खुद का अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की है
फोटो - पीटीआई

इसरो का एक बार में 105 सैटेलाइट प्रक्षेपण का रिकॉर्ड भी है। अंतरिक्ष के मामले में भारत अन्य देशों से पीछे नहीं है। भारत ने भी चांद और मंगल ग्रह पर अपना उपग्रह भेजा है। इसके अलावा भारत ने इसी साल अतंरिक्ष में एक सक्रिय उपग्रह को मिसाइल से मार गिराने का सफल परीक्षण भी किया है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

डॉक्टरों की सुरक्षा करे सरकार

पश्चिम बंगाल में डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर पिछले चार दिन से हड़ताल पर हैं। पूरे देश के डॉक्टर इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के तीसरे दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टरों को काम पर लौटने की चेतावनी दी थी लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा पर शायद ही कोई बात की हो। देश में डॉक्टरों से दुर्व्यवहार तथा हिंसा की खबरें आती रहती हैं। सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही लेकिन सरकार एस्मा लगा देती है जिससे कि वे अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर को भगवान माना जाता है क्योंकि वे मरीजों को नया जीवन देने में अपना योगदान देते हैं। डॉक्टरों के साथ हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई मौकों पर जब डॉक्टर अपना फर्ज निभाने में असफल हो जाते हों तब शायद मरीज के परिजन ऐसा कदम उठाते हों। सरकार को सर्वप्रथम डॉक्टरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और फर्जी डॉक्टरों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।